SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, Sports is a national Subject, not a State Subject.

MR. CHAIRMAN: Please, please.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, Guwahati is included in the proposal of 20 Smart Cities. So, my question will be restricted to Guwahati only, which has held very successful South Asian Games recently, an international sports event. So, in the sports arena, it is an important city. But, here, in the reply, it has been said that in the first Round of selected 20 Smart Cities, sports arena has not been included in the Smart City Proposals. I want to know from the hon. Minister whether he will take positive steps at different levels to include sports arenas in the second Smart City Proposals.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Chairman, Sir, in this regard we have already communicated to the concerned Ministry, and also our special request to create infrastructure facilities in those Smart Cities is always there.

*184. [The Questioner (SHRI K. K. RAGESH) was absent.]

Convictions under PWDV Act, 2005

*184. SHRI K. K. RAGESH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many people were convicted for domestic violence after the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 came into force;

(b) whether Government has any data about the changes occurred in the incidence and reporting of domestic violence after the enforcement of PWDV Act, 2005; and

(c) if so, the State-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) As per inputs provided by National Crime Records Bureau (NCRB), during 2014 a total of 13 persons have been convicted under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. NCRB has started collecting data on the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 only since 2014. State/UT-wise cases reported, cases charge-sheeted, cases convicted, cases conviction rate, persons arrested, persons charge-sheeted and persons convicted under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 during 2014 is given in the Statement-I.

Statement-I

State/UT-wise Cases Registered (CR), Cases Charge Sheeted (CS), Cases Convicted (CV), Cases Conviction Rate (CVR), Persons Arrested (PAR), Persons Charge Sheeted (PCS) and Persons Convicted (PCV) under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 during 2014

Sl. No.	State/UT	2014						
		CR	CS	CV	CVR	PAR	PCS	PCV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Andhra Pradesh	0	0	0	-	0	0	0
2.	Arunachal Pradesh	0	0	0	-	0	0	0
3.	Assam	1	1	0	-	1	1	0
4.	Bihar	112	52	2	40.0	123	65	3
5.	Chhattisgarh	0	0	0	-	0	0	0
6.	Goa	2	1	0	-	1	1	0
7.	Gujarat	2	2	0	0.0	2	2	0
8.	Haryana	4	5	0	0.0	3	8	0
9.	Himachal Pradesh	5	4	0	-	5	4	0
10.	Jammu and Kashmir	0	0	0	-	0	0	0
11.	Jharkhand	5	2	0	0.0	4	2	0
12.	Karnataka	0	0	0	-	0	0	0
13.	Kerala	140	106	2	12.5	116	115	2
14.	Madhya Pradesh	53	51	2	11.1	59	59	5
15.	Maharashtra	4	3	0	-	6	5	0
16.	Manipur	0	0	0	-	0	0	0
17.	Meghalaya	0	0	0	-	0	0	0
18.	Mizoram	0	0	0	-	0	0	0
19.	Nagaland	0	0	0	-	0	0	0
20.	Odisha	0	0	0	-	0	0	0
21.	Punjab	2	0	0	-	2	0	0
22.	Rajasthan	17	11	0	-	16	16	0
23.	Sikkim	0	0	0	-	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Tamil Nadu	4	3	0	0.0	4	3	0
25.	Telangana	1	1	0	-	3	3	0
26.	Tripura	0	0	0	-	0	0	0
27.	Uttar Pradesh	66	67	2	100	345	350	2
28.	Uttarakhand	0	0	0	-	0	0	0
29.	West Bengal	1	1	0	-	3	3	0
	TOTAL STATE(S)	419	310	8	17.4	693	637	12
30.	Andaman and Nicobar Islands	0	0	0	-	0	0	0
31.	Chandigarh	0	0	0	-	0	0	0
32.	Dadra and Nagar Haveli	0	0	0	-	0	0	0
33.	Daman and Diu	0	0	0	-	0	0	0
34.	Delhi UT	7	2	1	100.0	0	2	1
35.	Lakshadweep	0	0	0	-	0	0	0
36.	Puducherry	0	0	0	-	0	0	0
	Total UT(S)	7	2	1	100.0	0	2	1
	TOTAL (ALL INDIA)	426	312	9	19.1	693	639	13

Source: Crime in India
Note: Disposal of cases/persons by police/courts may include cases/persons of previous years also.
Cases Conviction Rate (CVR) = Cases Convicted/Cases in which trial completed x 100.

MR. CHAIRMAN: The questioner is not present. Any supplementaries?

श्री जावेद अली खानः माननीय सभापति जी, हमारे समाज में जितना पुराना इतिहास परिवार का या विवाह की इकाई का है, उतना ही पुराना इतिहास घरेलू विवादों का है, जो आगे चल कर घरेलू हिंसा को जन्म देते हैं। महिला सम्मान, महिला अधिकार, महिला जागृति, महिला संरक्षण, इन सारे विषयों से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि घरेलू हिंसा कानून के दुरूपयोग के भी बहुत सारे मामले प्रकाश में आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, जिसके जरिए यह पता किया जा सके कि घरेलू हिंसा के कितने झूठे मुकदमें दर्ज हुए या घरेलू हिंसा के कितने फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं? घरेलू हिंसा से संबंधित फर्जी या झूठे मुकदमे ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان:** مانینے سبھاپتی جی، ہمارے سماج میں جتنی پرانی تاریخ خاندان کی یا وِواہ کئ اکائی کی ہے، اتنی ہی پرانی تاریخ گھریلو وِوادوں کا ہے، جو آگے چل کر گھریلو تشدد کو جنم دیتے ہیں۔ مہیلا سمّان، مہیلا ادھیکار، مہیلا جاگری، مہیلا سنرکشنا، ان سارے موضوعات سے اپنیٰ سہمتی ظاہر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہونگا کہ گھریلو تشدد قانون کے دُراپیوگ کے بھی بہت سارے معاملے سامنے آتے ہیں۔

میں آپ کے مادھیم سے مانینے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کوئی ایسا میکینزم بنایا ہے، جس کے ذریعہ یہ پتہ کیا جاسکے کہ گھریلو تشدد کے کتنے جھوٹے مقدمے درج ہونے یا گھریلوتشدد کے کتنے فرضی مقدمے درج ہوتے ہیں؟ گھریلو تشدد سے متعلق فرضی یا جھوٹے مقدمے...(مداخلت)...

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, यह गलत तरीके का सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, आप सुन लीजिए। Please. ...(*Interruptions*)... No, no. Do not interfere. ...(*Interruptions*)... Do not interfere. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

श्री जावेद अली खानः मैंने सारे तथ्यों से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह सवाल पूछा है। ...(**व्यवधान**)... इसका दुरुपयोग गलत है।

†**جناب جاوید علی خان:** میں نے تو سارے تتھیوں سے اپنی سہمتی ویکت کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا ہے ...(مداخلت)... اس کا دُراُپیوگ غلط ہے۔

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. ...(*Interruptions*)... Let the question. ...(*Interruptions*)...

श्री जावेद अली खानः सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि घरेलू हिंसा कानून का कितना दुरुपयोग होता है, क्या इसका भी कोई आंकड़ा सरकार के पास है?

†**جناب جاوید علی خان:** سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گھریلو تشدد قانون کا کتنا دُراپیوگ ہوتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی آنکڑا سرکار کے پاس ہے؟

श्री किरन रिजिजुः चेयरमैन सर, यह मामला बहुत संवेदनशील है और सरकार के पास बहुत-से पक्ष आते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस या ध्यान महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी इज्जत किसी भी समाज के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए। उसमें किसी तरह का समझौता या देर नहीं की जा सकती है, लेकिन यह बात भी सही है कि कानून का कोई प्रोविजन होता है, तो उसका कभी-कभी गलत प्रयोग भी होता है और उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जब पिछली बार हमारे सामने ऐसी चीज़ आई कि समाज में कुछ ऐसे ग्रुप्स या एनजीओज हैं, जिन्होंने इस संबंध में रिप्रेजेंटेशंस दी हैं कि बड़ी मात्रा में इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। खासकर Dowry Act

† Transliteration in Urdu script.

और अन्य प्रोविजंस से जुड़े ऐसे मामले सामने आए हैं। उससे निपटने का प्रावधान या प्रक्रिया सरकार करेगी, लेकिन साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि महिला सुरक्षा को ही प्राथमिकता देकर काम करना चाहिए, तभी एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा।

श्रीमती झरना दास बैद्यः सर, इस प्रश्न में domestic violence के बारे में मंत्री जी ने जो लिखित जवाब दिया है, उसमें मैं देख रही हूं कि PAR 693 हुआ है, PCS 639 हुआ है और PCV 13 हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह जानना चाहती हूं कि domestic violence में जो अरेस्ट्स हुए हैं, उनमें इतना कम conviction क्यों है? वे कैसे छूट जाते हैं? जो लोग domestic violence में अरेस्ट हुए हैं, उनका आंकड़ा आपने दिया है, लेकिन उसके बाद मैं conviction का आंकड़ा देख रही हूं कि यह मात्र 13 है। मैं यह जानना चाहती हूं कि domestic violence से जुड़े इतने सारे आदमी कैसे छूट जाते हैं और वे क्यों छूट जाते हैं?

श्री किरन रिजिजुः सर, मैं इस पर थोड़ी-सी clarification देना चाहूंगा। यह ऐक्ट सिविल लॉ हो गया। हमने ये आंकड़े इसलिए पेश किए हैं, क्योंकि सवाल Protection of women from domestic violence से संबंधित है। सर, यह एक सिविल लॉ है, जो बहुत ही क्रिमिनल नेचर का नहीं होता है। जब हम क्रिमिनल केसेज़ की बात करेंगे, तो उसके आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। चूंकि सवाल किमिनल केसेज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमने ये आंकड़े दिए हैं। Protection of Women from Domestic Violence Act वर्ष 2005 में बना और वर्ष 2006 में इसके लागू होने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब घर में पति और पत्नी के बीच आपस में domestic violence होता है, तो वह compoundable होता है और यह मामला आपस में सुलझ भी जाता है, लेकिन अगर आप क्रिमिनल केसेज़ की बात करें, तो उनका आंकड़ा मैं बहुत विस्तार से दे सकता हूं। Protection of Women from Domestic Violence Act के अलावा Dowry Prohibition Act, Protection of Child Women Act और Illegal Trafficking का भी ऐक्ट होता है, जिनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मैंने यहां केवल civil portion का ही जिक किया है, इसलिए हमने इसमें PCV का आंकड़ा 13 दिखाया है।

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया, उसमें civil cases के बारे में बताया है, लेकिन महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, उस पर ध्यान देना बहुत ही important है। आपने जो आंकड़ा दिया है, उसके अनुसार वर्ष 2014 में पूरे देश में सिर्फ 13 लोग civil suit में convict हुए हैं। यह आंकड़ा कहता है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह एक गांव का आंकड़ा है या पूरे देश का आंकड़ा है? हम गांव से आते हैं और हर घर में घरेलू हिंसा होती है। अगर हमारे भाई यहां पर बोल रहे हैं कि कुछ महिलाएं गलत तरीके से इल्जाम लगाती हैं, तो मैं यह बताना चाहती हूं कि अगर आप इस तरह से बोलकर महिलाओं का अपना हक मांगने का भी अधिकार छीन लोगे, तो वे कैसे अपना अधिकार मांगेंगी?

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्रीमती रजनी पाटिलः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि देश में हर महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटना होती है, इसका conviction rate 19 परसेंट है, रजिस्टर्ड केस 426 हैं और जो fear of law है, जो कानून का भय है, वह लोगों में पैदा हो और यह हिंसा शुरू ही न हो ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयलः दुरुपयोग तो होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please ask your question.

श्रीमती रजनी पाटिलः जो fear of law है, जो कानून का भय है, इसके लिए क्या सख्त कदम उठाने के बारे में आपने सोचा है?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I think in the previous answer to the question I was unable to convince the hon. Members. If I give the total figure for all the crimes against women, it is going to be huge. I am referring to the question which is civil in nature. That is why the figure shown is less. So, please understand that. If you want to know this in detail, if you permit, I can talk about the criminal part also.

श्रीमती रजनी पाटिलः हम पूछ रहे हैं कि इसके लिए सख्त कानून बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री किरन रिजिजुः सर, मैं आपकी परमिशन से बताना चाहता हूं कि The Protection of Women from Domestic Violence Act में जो provision है, खास तौर से मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ज्यादातर विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के जो संबंधित अधिकारी होती हैं, जो सीडीपीओ होते हैं, वे ही एडिशनल पोस्ट सम्भालते हैं, ताकि वे फैसिलिटेट करें। They play the role of a facilitator for the victim and act as a bridge between the judiciary and the police, so that he or she gets justice. I want to confine myself to the civil nature of the crime which is normally there within a family. That is why the figure is less. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: The Minister should be told that violence is not civil ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः इसमें सिविल कहां है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: He should correct ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... One minute, please. ...(*Interruptions*)... This is not a debate. ...(*Interruptions*)... This is not a debate. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... This is not a debate. ...(*Interruptions*)...

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: Sir, how can violence be civil in nature? ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, if you permit me ...(*Interruptions*)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। This is not a debate. ...(*Interruptions*)... This is not a debate. This is not your question. ...(*Interruptions*)... This question is over. ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः सर, हिंसा के नाम पर ...(**व्यवधान**)... सर, हिंसा सिविल कैसे हो गयी? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... सत्यवत चतुर्वेदी जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Satyavratji, please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, if you permit me ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: This question is over. ...(*Interruptions*)... This question is over. ...(*Interruptions*)... You can have a fuller discussion on it. ...(*Interruptions*)... This is over. ...(*Interruptions*)...

श्री किरन रिजिजुः शैलजा जी, आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Satyavratji, please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, we need your protection. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... This is not your question. ...(*Interruptions*)... This is not going on record. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: *

SHRI KIREN RIJIJU: *

MR. CHAIRMAN: Let me say something. ...(*Interruptions*)... One minute, please. ...(*Interruptions*)... Let me say something. ...(*Interruptions*)... Give me one minute. If you read the answer, then you will notice that there is a huge problem in the country. The Act was made in 2005 and the collection of data started in 2014. Unmentioned here is when the rules were made to implement the Act.

So, we have a social problem which cuts across all sections of the society. You can have a debate on it. ...(*Interruptions*)... Let me go to the next question, which is Question No. 185. ...(*Interruptions*)... Question No. 185. ...(*Interruptions*)... This question is over. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I need your protection. ...(*Interruptions*)... Please try to understand. I am talking about the Act. If you quote the provisions of the IPC, then you invoke so many things. ...(*Interruptions*)... I am talking about the Act. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Read the question carefully.

---

* Not recorded.

...(*Interruptions*)... He is quoting the Act which is what the question is about. ...(*Interruptions*)... Please ask your Question No. 185. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: There are criminal acts and there are civil acts. You have to understand the difference. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: You are not understanding. ...(*Interruptions*)... Your answer says that. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Sharma Saheb, that is over. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... This is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, you have to give protection to the Member. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is not this Member's question. ...(*Interruptions*)... It is not her question. ...(*Interruptions*)... I am sorry. ...(*Interruptions*)... You can't. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Member has every right to object to it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Did you ask a supplementary question? ...(*Interruptions*)... No. ...(*Interruptions*)... Did you ask a supplementary question? ...(*Interruptions*)... No.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, after the question was over, he just said that. ...(*Interruptions*)... Please Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, what is the message going out from Rajya Sabha to the country? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the next question. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: You can give notice for further discussion. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Why are you doing this? ...(*Interruptions*)... If you want a debate on this, have a debate on this. ...(*Interruptions*)... Have a debate on this. ...(*Interruptions*)... Seljaji, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: You give notice for further discussion. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, it is about the use of language. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Seljaji, please don't. ...(*Interruptions*)... Will you please sit down? ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, please go through the records. ...(*Interruptions*)... The use of language by the Minister is highly objectionable. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Sharma Saheb, please. ...(*Interruptions*)... Can we discuss this matter a little later? ...(*Interruptions*)... Could you please sit down? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, he should not have said that. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, I object to the use of improper language. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Question No. 185. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I beg your pardon. What do you mean by "No, Sir"? ...(*Interruptions*)... I am taking up a question. ...(*Interruptions*)... Don't interrupt any further. ...(*Interruptions*)... I will clarify the matter to you after the Question Hour. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... The Chair is not expected to comment on questions and answers. ...(*Interruptions*)... One minute. ...(*Interruptions*)... Please let me point out something. ...(*Interruptions*)... The Act was made in 2005. ...(*Interruptions*)... One minute. ...(*Interruptions*)... Please keep quiet. The collection of data started in 2014. ...(*Interruptions*)... Just a minute. Think about it. It took you nine years to collect data and unmentioned in the answer is when the rules were made. They were not made in 2005. I do not know when the rules were made. But, they were certainly not made in 2005. So, let us not go into it. We will have a proper discussion on this when time is available. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, excuse me. I am not on this point.

MR. CHAIRMAN: You have not been given the floor.

KUMARI SELJA: My point is that the Minister has used objectionable language when we stood up. ...(*Interruptions*)... Sir, please understand my point. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: If you are talking about language, the record will be examined. ...(*Interruptions*)... Now sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Kalita, you have had your supplementary. ...(*Interruptions*)... You have a discussion by all means. ...(*Interruptions*)...

UN convention against torture

*185. SHRI AVINASH PANDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is planning to ratify the United Nations Convention Against Torture, 1997, to which India is a signatory;